भारत सरकार

जल संसाधन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1545

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2011 को दिया जाना है ।

.....

जल प्रबंधन

1545. प्रो. सैफुद्दीन सोज़ :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को जल संसाधनों के कमजोर प्रबंधक देशों में से एक माना जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि सिंगापुर जैसे देशों, जिनके पास हमारे जैसे बहुत अच्छे जल संसाधन नहीं हैं, ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर 'हां' में है, तो देश के जल प्रबंधन में सुधार हेतु क्या उपाय किये जाएंगे ?

उत्तर

जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वींसेंट एच. पाला)

(क) देश में जल प्रबंधन की समस्या वर्षा के जल का स्थान और समय के अनुसार समान वितरण न होने, जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण गंभीर हो गई है । वर्ष 2011 की जनगणना में दी गई जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगभग 1,545 घन मीटर प्रति वर्ष आंकी गई है जिससे भारत जल की समस्या वाला देश बन गया है । फाल्केनमार्क जल समस्या संकेतक के अनुसार प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1,700 घन मी. प्रति वर्ष से कम होना जल की समस्या की अवस्था का सूचक है ।

(ख) एवं (ग) कम भूमि वाले सिंगापुर में जल आवाह क्षेत्र हेतु भूमि का प्रबंधन और जल के मुख्य स्रोतों के रूप में चार राष्ट्रीय नलों को सामाजिक-आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुसार अतिनिपुणता से संतुलित किया जाना चाहिए । तथापि, प्रत्येक देश की अपनी अनोखी स्थिति और परिस्थितियां होती है, जिनकी

तुलना अन्य से नहीं की जा सकती है । भारत मे जल राज्य का विषय है तथा जल संसाधन परियोजनाओं की संकल्पना, आयोजना, कार्यान्वयन, विकास और प्रबंधन हेतु आवश्यक उपाय करना राज्य सरकारों का प्राथमिक दायित्व है । तथापि, भारत सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों नामत: "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम(एआईबीपी)" "कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडी एवं डब्ल्यूएम) कार्यक्रम" और "जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) द्वारा राज्य सरकारों को जल संसाधनों के सतत विकास और दक्ष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है । जल की वृहद अस्थायी परिवर्तनशीलता का समाधान करने के लिए सक्रिय क्षमता को स्वतंत्रता के समय 15.6 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) से बढाकर वर्तमान स्तर 253.388 बीसीएम किया गया है । सरकार उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए देश के जल की समस्या वाले क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है ।

राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन द्वारा जल का संरक्षण करने, बर्बादी कम करने तथा राज्यों के आसपास और भीतर जल का अधिक समान वितरण करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्स से प्रारंभ किया गया है । एनडब्ल्यूएम के अंतर्गत XII वीं योजना के अंत तक जल उपयोग दक्षता में 20% सुधार करने की परिकल्पना की गई है ।

*****